



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने झुंझुनू, आबू रोड और डूंगरपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रदेश में हवाई सुविधाओं की समीक्षा की

कोटा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, झुंझुनू, आबू रोड, डूंगरपुर हवाई पट्टी विस्तार के निर्देश दिये

जयपुर, 28 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हवाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार ने दूरगामी निर्णय लिए हैं। इससे पर्यटन, शिक्षा एवं व्यापारिक गतिविधियों में इज़ाफा होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अपेक्षित गति मिलेगी। मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट महत्वपूर्ण साबित होगा। इस एयरपोर्ट के विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य एमओयू हो चुका है। उन्होंने

- मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में जयपुर एयरपोर्ट की क्षमता 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रतिवर्ष करने का कार्य तेज गति से करने के निर्देश दिये।
- हरियाणा से सालासर और खाटूरश्याम जी हवाई सुविधा के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।

अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ईएचवी लाइन शिफ्टिंग और आरआरवीपीएनएल की लाइन शिफ्टिंग के कार्य में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर एयरपोर्ट पर बनने जा रहे स्टेट टर्मिनल पर विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएं और टर्मिनल की बिल्डिंग के स्थापत्य में जयपुर की विरासत की

दिए। साथ ही, प्रतापगढ़ और हमीरगढ़ में फ्लाईंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (एफटीओ) के कार्यों में भी गति लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा से सालासर और खाटूरश्यामजी के लिए हवाई सुविधा और एयर एंबुलेंस सुविधा के अन्तर्यन और विस्तार की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एयर एंबुलेंस की सुविधा से दूरस्थ स्थानों के लिए आपातकालीन चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। बैठक में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दत्त, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

भाजपा अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया टली

पहलगाम आतंकी हमले के बाद बने हालात को देखते हुए यह फैसला किया गया है

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पार्टी के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टालने का फैसला किया है। पार्टी के सूत्रों के अनुसार, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बने हालात को देखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर टाल दिया गया है। पार्टी ने जगत प्रकाश नड्डा को कुछ समय के लिए अध्यक्ष बनाये रखने का भी फैसला किया है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कब तक के लिए टाले गये हैं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। पहले बताया गया था कि भाजपा

- अभी यह पता नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया फिर से कब शुरू होगी।

का नया अध्यक्ष अप्रैल के अंत तक या मई की शुरुआत में चुन लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पार्टी नेतृत्व ने संगठनात्मक चुनाव को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। पार्टी महसूस करती है कि इस समय संगठन की स्थिरता और सरकार की नीति को मजबूती से आगे बढ़ाना जरूरी है। ऐसे में पार्टी के आंतरिक चुनाव को

फिलहाल प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। नए अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख की घोषणा बाद में होगी। उल्लेखनीय है कि भाजपा के संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तब तक नहीं हो सकता, जब तक आधे से ज्यादा राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे न हो जाएं। अभी तक 14 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं और बाकी राज्यों में प्रक्रिया चल रही है। नड्डा का कार्यकाल पहले ही बढ़ाया जा चुका है, और वह फिलहाल अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। नड्डा को वर्ष 2019 में भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद जनवरी 2020 में वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे।

तहव्वुर राणा की हिरासत अवधि बढ़ी

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। दिल्ली में पटयाला हाउस कोर्ट की एक विशेष अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अजी पर मुंबई में आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की हिरासत की अवधि 12 दिन के लिए बढ़ा दी। मुंबई में 26 नवंबर के भयावह आतंकवादी हमलों की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार राणा को इससे पहले अदालत ने 18 दिन की रिमांड पर

- 26 नवम्बर को गिरफ्तार राणा की 18 दिन की हिरासत पूरी होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने फिर से उसे 12 दिन की हिरासत में भेज दिया।

एनआईए को सौंपा था। राणा को भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत अदालत की अनुमति से इसी माह विशेष विमान से नयी दिल्ली लाया गया था। एनआईए ने नयी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही उसे 10 अप्रैल को हिरासत में ले लिया था। उसी शाम उसे दिल्ली की विशेष अदालत में पेश कर जांच एजेंसी ने उससे पूछताछ के लिए 18 दिन की रिमांड पर ले लिया था। रिमांड की अवधि पूरी होने पर आज उसे अदालत में पेश किया गया था।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) यह स्पष्ट है कि उसकी सहानुभूति किस ओर है। चीन ने पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के निर्माण में बड़ी मात्रा में निवेश किया है। अगर गंभीर युद्ध की स्थिति आती है, तो उन सारे बुनियादी ढांचों, जो चीन के पैसों से बने हैं और जिनकी लागत अब तक पाकिस्तान ने चुकाई नहीं है, को नुकसान से बचना चीन की प्राथमिकता होगी।

इसके अलावा, विवादित क्षेत्र कश्मीर में भी चीन की गहरी दिलचस्पी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर उसकी मुख्य ट्रांसपोर्ट लाइनें गुजरती हैं। इस क्षेत्र में किसी भी बड़े संघर्ष से ये संरचनाएं और चीनी हित निश्चित

रूप से प्रभावित होंगे। आखिरकार, इन्हीं क्षेत्रों से चीन, अरब सागर पर स्थित अपनी द्वीपसमूह और अकेले लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिका के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। ट्रंप अब अपने द्वारा बनाए गए घरेलू संकटों में इस कदर उलझ गए हैं कि उनके पास दक्षिण एशिया की चिंता करने का समय नहीं है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने पद्म सम्मान प्रदान किए

- राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 71 व्यक्तियों को पद्म अवॉर्ड दिए गए। इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई थी।

संग्रहालय का भ्रमण भी करेंगे। समारोह में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ , प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेन्द्र यादव तथा अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

- अतः भारत भी पाकिस्तान पर “स्विफ्ट” धड़ाधड़ “वॉफ” करने के पक्ष में है, जिससे पाकिस्तान जवाबी कार्यवाही कर ही नहीं पाये। भारत को अपने ही दम पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई के लिये तैयार रहना चाहिए और लम्बे युद्ध के रास्ते नहीं जाना चाहिए।

अगर किसी देश ने भारत के पक्ष में निर्णायक और सकारात्मक संकेत दिए हैं, तो वह रूस है। लेकिन रूस की भी अपनी समस्याएं हैं। यूक्रेन का संकेत सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और अब रूस पर ही हमले तेज हो रहे हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि रूस 8 से 10 मई तक एकतरफा युद्धविराम की बात कर रहा है। रूस ने यूक्रेन से प्रत्यक्ष बातचीत के भी कुछ आश्वासन दिए हैं। यह पहली

‘हमने “टू नेशन थ्योरी” को 1947 में ही दरिया में बहा दिया था’

अब्दुल्लाह ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष पर कटाक्ष किया, “टू नेशन थ्योरी” को पुनः उठाने पर

—डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 28 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लाह ने बेहद कठोर बयान जारी किया और इस्लामाबाद को फटकारते हुए कहा कि कश्मीरियों ने 1947 में ही द्विराष्ट्र सिद्धांत को दरिया में बहा दिया था और कह दिया था कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा।

नैशनल कॉंग्रेस के चेयरमैन ने कहा कि, वे हमेशा पाकिस्तान के साथ वार्ता के पक्ष में रहते थे पर अब चाहते हैं कि केन्द्र सरकार पाकिस्तान पर कड़ी कार्यवाही करे ताकि ऐसे हमले दोबारा न हो। न्यूज़ एजेंसी के अनुसार अब्दुल्लाह ने कहा कि, मैं हमेशा पाकिस्तान के साथ वार्ता की बात करता था पर हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है?

- फारुख अब्दुल्लाह ने कहा कि वे पहले सदा पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में रहते थे, पर, अब वे केवल यह चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार ऐसी सख्त कार्यवाही करे, पाकिस्तान के खिलाफ कि पहलगाम जैसी हरकतें दुबारा कभी न हों।

क्या हम न्याय कर रहे हैं? बालकोट नही, आज देश ऐसा एक्शन चाहता है ताकि ऐसे हमले दोबारा न हों” द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करते हुए डॉ. अब्दुल्लाह ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया और कहा जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में दो राष्ट्र वाले सिद्धांत को ठुकरा दिया था और आज भी वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। अब्दुल्लाह ने कहा, “हमें खेद है कि हमारा पड़ोसी यह नहीं समझता है कि उसने ईसानियत का कल्ल कर दिया है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा

करने से हम पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे तो हमें यह गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। हम 1947 में उनके साथ नहीं गए थे तो अब क्यूं जाएंगे? हमने उस समय ही दो राष्ट्र वाले सिद्धांत को दरिया में बहा दिया था और आज भी हम इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई हम सब एक हैं। हम उन्हें करारा जवाब देंगे।” पहलगाम हमले के बाद आया फारुख अब्दुल्लाह का यह बयान पाक सेनाध्यक्ष जनरल असीम मूनिर के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने

दो राष्ट्र के सिद्धांत का जिक्र किया था। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए 16 अप्रैल को जनरल मूनिर ने कहा था कि भारत के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा रहेगा।” उन्होंने कहा, “यह हमारे गले की नस था और रहेगा, हम इसे नहीं भूलेंगे।” उसी भाषण में उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कहा लोग अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानियां सुनाएं ताकि वे यह न भूलें कि वे हिन्दुओं से अलग हैं। उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा, आप लोग अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी सुनाएं ताकि वे यह न भूलें कि हमारे पूर्वज सोचते थे कि हम हिंदुओं से हर प्रकार से अलग हैं।

‘संसद का विशेष सत्र...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कि वे इन देशों में अपने रिपोर्टर भेजें, जहाँ मोदी पाकिस्तान को भला-बुरा कह सकते हैं। संसद सत्र बुलाये जाने की माँग पर, सरकार से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। रोचक बात यह है कि कांग्रेस के अन्दर कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक वर्ग, उस तौर-तरीके की आलोचना कर रहा है, जिस तरीके से पार्टी ने नेतृत्व ने मोदी सरकार को व्यापक समर्थन दिया है, किन्तु गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की माँग नहीं की, जो कश्मीर, आन्तरिक सुरक्षा गुप्तचर विभाग के कर्ता-धर्ता हैं। पहलगाम में सुरक्षा तथा खुफिया विफलता के कारणों को लेकर सवाल क्यों नहीं किये जा रहे हैं।

एक कांग्रेस नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि कहीं यह नैशनल हैरल्ड केस तथा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ केसों का परिणाम तो नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस अब संसद के विशेष सत्र की माँग करके, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की आलोचनापूर्ण प्रतिक्रिया का डैमेज-कन्ट्रोल कर रही हो।

बीकेयू ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) आतंकवादियों और भारत विरोधी तत्वों को ताकत देते हैं। उन्होंने कहा कि देश व दुश्मनों का खाल्ना ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने भारत विरोधी ताकतों की जाँच करने का आग्रह किया।

सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी चैनल पर अश्लील सामग्री के प्रसारण के खिलाफ नोटिस जारी किया

ये नोटिस केन्द्र सरकार नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम, ऑल्ट बालाजी तथा कुछ अन्य चैनल्स को दिए गए हैं

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री को लेकर नियमन की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने पर सहमति जताई और कहा कि इस मुद्दे ने ‘गंभीर चिंताएं’ पैदा की हैं।

न्यायमूर्ति जी.ओ.ए. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने केंद्र सरकार और नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम, ऑल्टबालाजी, उल्टू डिजिटल था, बल्कि सोशल मीडिया तथा ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ-साथ सोशल मीडिया जगत की दिग्गज कंपनी एक्स कॉर्प, गूगल, मेटा इंक और एप्पल को

- सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जनहित याचिकाओं पर विचार करते हुए दिया। यह याचिका पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर, संजीव नेवार, सुदेष्णा भट्टाचार्य, शताब्दी पांडे, स्वाति गोयल ने दायर की थी।

नोटिस जारी किया। इस मामले को अन्य समान लंबित याचिकाओं के साथ भी टैग किया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इस बात पर जोर दिया कि याचिका प्रतिकूल नहीं थी, बल्कि सोशल मीडिया तथा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के अनियंत्रित प्रसार के बारे में ‘वास्तविक चिंता’ जताई गई थी।

न्यायालय के प्रश्न का उत्तर देते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वीकार किया कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा उजागर की गई कुछ चिंताओं से सहमत हैं। प्रस्तुत कार्यक्रमों की सूची की समीक्षा करने के बाद, उन्होंने पाया कि नियमित शो में भी अश्लील सामग्री प्रसारित की गयी थी और कुछ कार्यक्रमों को इतना विकृत बताया कि दो सम्मानित व्यक्ति भी एक साथ बैठकर उन्हें नहीं

देख सकते। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, यह याचिका ओटीटी प्लेटफार्मों और सोशल मीडिया पर विभिन्न आपत्तिजनक अश्लील और अभद्र सामग्री के प्रदर्शन के संबंध में एक महत्वपूर्ण चिंता पैदा करती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि सामग्री विकृति के प्रदर्शन के साथ बढ़ती है। उन्होंने कहा कि कुछ और विनियमन विचाराधीन हैं। जनहित याचिका पत्रकार एवं पूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर, संजीव नेवार, सुदेशना भट्टाचार्य मुखर्जी, शताब्दी पांडे और स्वाति गोयल द्वारा दायर की गई थी।

पाकिस्तान के 16 यू ट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। सरकार ने भारत, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के बारे में भड़काऊ, झूठे, भ्रामक और सांप्रदायिकत सद्भावना को बिगाड़ने वाली सनसनीखेज सामग्री का प्रसारण करने वाले पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इसके अलावा इरशाद भट्टी, बी ओ एल न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान रेरेरेन्स, समा स्पोर्ट्स ,जीएनएन, उजैर क्रिकेट , उमर चीमा एक्सक्लूसीव , असमा सिराजी और मुनीब जैस यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है।

भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद पर मुहर

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच भारत और फ्रांस की सरकारों ने सोमवार को यहां फ्रांस के साथ 63 हजार करोड़ रूपये की लागत से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये।

रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबास्टियन लेकोर्नु ने इस सौदे पर हस्ताक्षर किये।

रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबास्टियन लेकोर्नु ने इस सौदे पर हस्ताक्षर किये।

रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबास्टियन लेकोर्नु ने इस सौदे पर हस्ताक्षर किये।

‘आप व्यर्थ के जोशीले, भड़काऊ भाषण देने से...

समय सीमा को लेकर पूरी तरह सुनिश्चित होना होगा। यह एक संक्षिप्त, लेकिन बेहद तीव्र और दबावकारी हमला होना चाहिए, जिससे पाकिस्तान के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही न बचे। इस समय ऐसी योजना बनाना अनुचित नहीं है। पाकिस्तान युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि युद्ध के लिए विशाल आर्थिक संसाधनों की जरूरत होती है। एक दिवालिया देश युद्ध का खर्च नहीं उठा सकता। उसके पास हथियारों के लिए पैसे भी नहीं हैं। पाकिस्तान इस समय फंड के लिए चारों तरफ हाथ फैला रहा है। पाकिस्तानी सेना की स्थिति शायद अब तक की सबसे कमजोर है, उसकी प्रतिष्ठा, सैनियर सैन्य अधिकारियों के

साथ जो हुआ, और सेना की आंतरिक राजनीति के कारण बुरी तरह धूमिल हो गई है। सेना, वायुसेना और नौसेना के सीनियर मोस्ट लोगों ने स्वयं को सुविधाजनक सेवा विस्तार (सर्विस एक्स्टेंशन) दे रखे हैं। सत्ता के उच्चतम स्तर पर इस तरह की चिपक कर रहने की प्रवृत्ति ने निश्चित ही कई अधिक योग्य जूनियर अधिकारियों को निराश किया है, जो उच्च पदों पर आने की आशा लगाए हुए थे। परस्पर जुड़ी घटनाओं और सितारों का इस तरह का क्रम भारत द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए अनुकूल है। परंतु सवाल यह है कि क्या भारत इस समय इतनी बड़ी, तेज और दबदबा कायम करने वाली पहल के लिए वास्तव में तैयार है?